जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

जालोर

Rashtradoot

फोनः- 226422, 226423 फैक्सः- 02973-226424 वर्षः 20 संख्याः 269 प्रभात जालोर, सोमवार 5 जनवरी, 2026 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

उपराष्ट्रपति डेल्सी ने वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला

वेनेज़ुएला सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश ने लोगों से अमेरिकी कार्यवाही का विरोध करने के लिए कहा

- **मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रोड्रिग्ज़ ने मंत्रियों व अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सत्र की अध्यक्षता की तथा अमेरिकी ऑपरेशन को अंतर्राष्ट्रीय कानून व वेनेज़ुएला की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया।**

काराकास, 04 जनवरी। वेनेज़ुएला के सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शनिवार देर रात उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने तत्काल प्रभाव से कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाल लिया है।

यह आदेश अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, के तहत राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सैनिकों द्वारा गिरफ्तारी के बाद आया।

सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कैरिस्लिया रोड्रिग्ज़ ने सरकारी टीवी चैनल वीटीवी पर प्रसारित एक बयान में कहा था, "राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण से उत्पन्न असाधारण स्थिति को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि गणतंत्र की कार्यकारी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक क्षमता में राष्ट्रपति पद की सभी शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को संभालें। यह निर्णय प्रशासनिक निरंतरता और राष्ट्र की व्यापक रक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।"

वेनेज़ुएला का संविधान अनुच्छेद 233 और 234 के तहत ऐसी स्थितियों का प्रावधान करता है, जो राष्ट्रपति की अस्थायी या पूर्ण अनुपस्थिति की स्थिति में उपराष्ट्रपति को पदभार संभालने की अनुमति देते हैं।

मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोर्स को हिरासत में लिए जाने के कुछ ही घंटों बाद, जस्टिस रोड्रिग्ज़ ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय रक्षा परिषद के सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने मादुरो दंपति की तत्काल रिहाई की मांग की और अमेरिकी ऑपरेशन की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून और वेनेज़ुएला की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया।

जस्टिस रोड्रिग्ज़ ने इस बात पर जोर दिया कि मादुरो ही वेनेज़ुएला के एकमात्र वैध राष्ट्रपति हैं। उन्होंने वेनेज़ुएला के लोगों से इस ऑपरेशन का विरोध करने का आग्रह किया और मध्य अमेरिकी देशों की सरकारों से इसकी निंदा करने की अपील की।

सुप्रीम कोर्ट ने वेनेज़ुएला के लोगों और क्षेत्र के खिलाफ अमेरिका द्वारा किए गए गंभीर सैन्य हमले और मादुरो और उनकी पत्नी के अपहरण की कड़ी निंदा की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेरिकी कार्रवाई वेनेज़ुएला के संविधान, अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य वेनेज़ुएला के रणनीतिक संसाधनों पर कब्जा करना है।

चीन ने वेनेज़ुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए अमेरिका से मांग की है कि वह मादुरो दंपती को तत्काल रिहा करे। चीन ने चेतावनी दी है कि किसी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ बल का ऐसा प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। चीनी विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में अमेरिका से वेनेज़ुएला की सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें बंद करने और विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकालने का आग्रह किया गया है।

इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) ने शनिवार को घोषणा की कि वह वेनेज़ुएला के खिलाफ अमेरिकी अभियान पर सोमवार को एक आपातकालीन बैठक आयोजित करेगी।

कांग्रेस ने राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी पर कड़ी आपत्ति जताई

नयी दिल्ली, 04 जनवरी। वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में गिरफ्तारी पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस सैन्य हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन करार दिया है।

- **महासचिव जयराम रमेश ने सैन्य हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन बताया।**

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को आधिकारिक बयान जारी कर अमेरिका की कार्रवाई को वैश्विक सिद्धांतों के विरुद्ध बताया।

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पिछले 24 घंटों में वेनेज़ुएला को लेकर अमेरिका द्वारा की गई कार्रवाइयों पर अत्यंत गंभीर चिंता व्यक्त करती है। अंतरराष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धांतों का इस तरह से एकतरफा उल्लंघन नहीं किया जा सकता।"

कांग्रेस का यह बयान वैश्विक संप्रभुता और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के प्रति पार्टी के पुराने रुख को दोहराता है।

पाकिस्तानी आकाओं से संपर्क के लिए घोस्ट सिम का उपयोग कर रहे हैं आतंकी

लाल किला ब्लास्ट केस की जाँच में यह चौंकाने वाला तथ्य उजागर हुआ

- **दूरसंचार विभाग ने इस संदर्भ में आदेश जारी किया है। वाट्सऐप, टेलीग्राम व सिग्नल जैसी ऐप आधारित कम्यूनिकेशन सर्विस को अब हमेशा डिवाइस में लगे एक एक्टिव फिजिकल सिम कार्ड से जुड़ा रहना होगा।**

नई दिल्ली, 04 जनवरी। दिल्ली के लाल किले के पास पिछले साल 10 नवंबर को हुए धमाके की जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। पता चला है कि एक सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में रहने के लिए घोस्ट सिम कार्ड और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल कर रहा था। ये आतंकी बहुत पढ़े-लिखे थे, जिनमें डॉक्टर भी शामिल थे। वे अपनी पहचान छिपाने के लिए गैर-कानूनी तरीके से हासिल किए गए या धोखाधड़ी से जारी करवाए गए सिम कार्ड और कई मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते थे।

इस जांच के नतीजों के आधार पर ही दूरसंचार विभाग ने 28 नवंबर को एक बड़ा आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक, वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिग्नलजैसे ऐप-आधारित कम्युनिकेशन सर्विस को हमेशा डिवाइस में लगे एक एक्टिव फिजिकल सिम कार्ड से जुड़ा रहना होगा।

सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, यह एक ऐसा मोबाइल कनेक्शन होता है जिसे गैर-कानूनी तरीके से जारी किया जाता है या धोखाधड़ी से एक्टिवेट किया जाता है, और यह असली यूजर से जुड़ा नहीं होता।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में इस मॉड्यूल की ओर से अपनाए जाने वाले एक खास, दो फोन वाले तरीके का खुलासा हुआ। हर आतंकी के पास दो से तीन मोबाइल फोन होते थे। एक मोबाइल उनके अपने नाम पर रजिस्टर्ड होता था, उसका इस्तेमाल वे अपनी रोजमर्रा की निजी और पेशेवर बातचीत के लिए करते थे ताकि किसी को शक न हो। दूसरा फोन, जिसे आतंकी फोन कहा गया, उसका इस्तेमाल वे सिर्फ पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से वॉट्सऐप और टेलीग्राम के जरिए एन्क्रिप्टेड तरीके से बात करने के लिए करते थे।

अधिकारियों ने बताया कि इन दूसरे फोन में इस्तेमाल होने वाले सिम कार्ड उन आम नागरिकों के नाम पर जारी किए गए थे जिनके आधार डिटेल्स का दुरुपयोग किया गया था। इसी के साथ, जम्मू और कश्मीर पुलिस ने भी एक अलग रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल करके सिम कार्ड जारी किए जा रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में मुजम्मिल गनाई और अदील राथर शामिल थे। वहीं, एक मुख्य आरोपी डॉ. उमर-उन-नबी लाल किले के पास विस्फोटकों से लदे वाहन में गाड़ी चलाते समय मारा गया था। पाकिस्तान में बैठे आकाओं की पहचान उकासा, फैजान और हाश्मी जैसे कोड नामों से हुई।

कांग्रेस व इंडिया गठबंधन 2026 में एक चौराहे पर खड़े हैं, दिशा भ्रम के कारण?

यह दिशा भ्रम का जाल तोड़ने के लिए, आवश्यक है कि 2026 में कांग्रेस को नए सिरे से राजनीतिक रणनीति बनानी होगी तथा राजनीतिक "जिद" छोड़कर वोटर से फिर जुड़ने का प्रयास करना होगा

- जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **कांग्रेस की ट्रेजेडी यह है कि उसके समक्ष मुद्दों की कमी नहीं है, पर, अंतर विरोध की संख्या, मुद्दों से कहीं ज्यादा है।**
- **कांग्रेस एक भाजपा विरोधी पार्टी बनकर रह गई है और उसकी पहचान अब सुदृढ़ राजनीतिक विकल्प के रूप में फिर से उभारनी पड़ेगी।**
- **वाकई में ऐसा लगता है, यह राजनीतिक विश्लेषण कांग्रेस विरोधी तत्वों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। पर, इसे यह संज्ञा देकर नज़रअदांज न करके उठाये गए मुद्दों पर गंभीरता से सोचना तो चाहिए ही।**

नई दिल्ली, 4 जनवरी। यह तीखा और बेबाक विश्लेषण कहता है कि "इंडिया" ब्लॉक, खासकर कांग्रेस, खुद की बनाई हुई उलझनों के जाल में फंसा हुआ है। बार-बार की चुनावी हार के बावजूद, विपक्ष अपनी रणनीति बदलने को तैयार नहीं है और ईवीएम के फर्जीवाड़े की कहानी, पहचान की राजनीति और विदेशी स्वीकार्यता जैसे खारिज हो चुके मुद्दों पर अड़ा हुआ है।

अपने सिकुड़ते भौगोलिक दायरे से लेकर विचारधारा पर चयनात्मक आक्रोश, संसद में व्यवधान डालने और पार्टी नेतृत्व को लेकर गांधी परिवार के भ्रामक संकेतों तक, कांग्रेस मतदाताओं की असलियत से दिन पर दिन कटती जा रही है। इस विश्लेषण का कहना है

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्रियंका गांधी असम स्क्रीनिंग कमेटी की प्रमुख बनीं

नयी दिल्ली, 04 जनवरी। कांग्रेस ने वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख नियुक्त किया है।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के लिए बीके हरिप्रसाद को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया है। केरल के लिए यह जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री, और तमिलनाडु और पुडुचेरी की जिम्मेदारी टीएस सिंह देव को दी गई है।

- **हरिप्रसाद को पश्चिम बंगाल, मधुसूदन मिस्त्री को केरल तथा टी.एस. सिंह देव को तमिलनाडु की जिम्मेदारी सौंपी गई है।**

वाड्रा को पहली बार पार्टी ने स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी है। इस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ममदानी के उमर खालिद को लिखे हस्तलिखित नोट ने अमेरिकी सिनेटरों को प्रेरित किया

अमेरिका के इन जनप्रतिनिधियों ने भारत के राजदूत मोहन क्वात्रा को पत्र लिखकर चिंता जताई, उमर खालिद पाँच साल से भारत में जेल में है तथा अभी उसे न तो चार्जशीट दी गई है और न ही सुनवाई शुरु हुई है

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **जैसा कि विदित ही है, उमर खालिद, शारजील इमाम, गुल फिशा फातिमा व मीरान हैदर, 2020 के दिल्ली दंगों में भारी "साजिश" रचने के आरोप में जेल में हैं, यू.ए.पी.ए. कानून के अंतर्गत।**
- **भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी व भारतीय राजदूत क्वात्रा को पत्र लिखने वाली अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य जैन शकाओस्की मिलकर भारत विरोधी अभियान चलाते आए हैं तथा राहुल गांधी का नाम सदा उभरकर आता है, जब भी विदेश में भारत विरोधी किसी गतिविधि की कोई खबर आती है।**

नई दिल्ली, 4 जनवरी। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर ज़ोहरान ममदानी ने जेल में बंद भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता उमर ख़ालिद के लिए तेज़ और निष्पक्ष मुकदमे की माँग करते हुए, नरेन्द्र मोदी सरकार के खिलाफ एक कूटनीतिक अभियान छेड़ दिया है। ममदानी का ख़ालिद के नाम हाथ से लिखा नोट जब सोशल मीडिया पर डाला गया, उसके बाद अमेरिका के आठ सांसदों ने वॉशिंगटन में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को एक पत्र भेजा। इसमें उन्होंने छात्र नेता उमर ख़ालिद की बिना ट्रायल के लंबे समय से चल रही हिरासत पर चिंता जताई, जिन्हें लगभग पाँच साल से यूएपीए कानून के तहत जेल में रखा गया है।

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सांसद जेम्स पी. मैकगवर्न और जैमी रैस्किन, सीनेटर क्रिस वैन होलन और पीटर वेल्च तथा कांग्रेस सदस्य प्रमिला जयपाल, रशीदा तलैब, लॉयड डॉगेट और जेन शाकॉव्स्की शामिल हैं।

दूसरी ओर, भाजपा ने इसे "भारत विरोधी अनर्थकारी साजिश" करार देते हुए आरोप लगाया है कि इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल हैं और यह साजिश अमेरिका की धरती पर रची गई है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 2024 में राहुल गांधी और जान शाकॉव्स्की की मुलाकात को कांग्रेस नेता के भारत विरोधी संबंधों का सबूत बताते हुए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी, शाकॉव्स्की और भारत विरोधी रुख रखने वाली इल्हान ओमर की एक तस्वीर पोस्ट की। भंडारी ने कहा, "जब भी विदेशों में भारत विरोधी कहानी चलती है, तो पृष्ठभूमि में राहुल गांधी का नाम सामने आता है। जो लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं, चुनी हुई सरकार को कमज़ोर करना चाहते हैं और भारत विरोधी आतंक सम्बन्धी कानूनों को कमज़ोर करना चाहते हैं, वे अनिवार्य रूप से उनके आसपास ही जुटते हैं।

भंडारी ने आगे दावा किया कि राहुल की 2024 में शाकॉव्स्की और ओमर से मुलाकात का संबंध विदेशों में कानूनी प्रयासों से था। उन्होंने 2025 में शाकॉव्स्की द्वारा पेश किए गए "कॉम्बैटिंग इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया एक्ट" का हवाला

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

डेरा प्रमुख राम रहीम को फिर से 40 दिन की पैरोल मिली

नयी दिल्ली, 04 जनवरी। अपनी दो शिष्याओं के साथ बलात्कार के मामले में 20 साल की जेल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिनों की पैरोल दी गई है।

- **अगस्त 2017 में बलात्कार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से यह 15वीं बार होगा जब राम रहीम को पैरोल या फरलो पर जेल से रिहा किया जाएगा।**

बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी राम रहीम हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। उसके पैरोल को रोहतक संभागीय आयुक्त ने मंजूरी दी है और उम्मीद है कि उसे रविवार या सोमवार को रिहा कर दिया जाएगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय फायनैंशियल एजेंसियां अगले दो दशक भारत की ग्रोथ के नाम लिख रही हैं

इस समाचार की ध्वनि कर्णप्रिय और सुखद तो है, पर पूर्णतया सत्य होगी, यह अभी पूरे विश्वास से नहीं कहा जा सकता

-सुकुमार साह-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

- **आई.टी. सैक्टर में भारत की भारी सफलता को बड़ा आधार माना जाता है, भारत के अगले दो दशक में छाने का। पर, इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इस क्षेत्र में भारत की सफलता की काफी कुछ वजह भारत में आई.टी. प्रोफेशनल्स की प्रचुर मात्रा है।**
- **पर, अब, विश्व का आई.टी. सैक्टर बदल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बड़ी-बड़ी कंपनियां अब छोटे-छोटे आई.टी. प्रोफेशनल्स की कंपनियों के साथ काम करने में ज्याद विश्वास करने लगी हैं और प्रचुर मात्रा में आई.टी. प्रोफेशनल होना कोई खास महत्व की बात नहीं रह गई। इन "हाईली एकैडमिक प्रोफेशनल्स" के छोटे-छोटे ग्रुप को जब काम दिया जाता है तो वे बिना बड़ी कंपनियों के "लाग-लपेट" के काम करते हुए जल्दी समाधान ढूंढ़कर पेश कर देते हैं।**

नई दिल्ली, 4 जनवरी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले दो दशकों में भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक वृद्धि-इंजनों में से एक के तौर पर उभरेगा। इसके पीछे सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में दबदबा, तेज़ डिजिटलाइज़ेशन, फलता-फूलता स्टार्ट-अप, इकोसिस्टम और अनुकूल जनसांख्यिकी (डैमोग्राफिक्स) जैसे कारण बताए जाते हैं। हाल की एक अर्न्स्ट एंड यंग (ई.वाय.) रिपोर्ट भी लगातार ऊँची वृद्धि की तस्वीर पेश करती है और कहती है कि भारत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दुनिया का दफ़्तर बनने और ग्लोबल वैल्यू चेन का एक प्रमुख केन्द्र बनने की अनोखी स्थिति में है। लेकिन गहराई से देखने पर लगता है कि ये कारक भले ही वास्तविक हों, लेकिन जितने मज़बूत बताए जाते हैं, उतने स्थायी और भरोसेमंद नहीं हैं।

भारत का ग्लोबल आई.टी. और सर्विस हब के रूप में उभरना उसकी दीर्घकालिक कहानी का सबसे मज़बूत स्तंभ माना जाता है। समय के साथ यह उद्योग सस्ती आउटसोर्सिंग से आगे बढ़कर, अधिक वैल्यू वाली डिजिटल इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग और इनोवेशन पर आधारित काम तक पहुँचा है। लेकिन वैश्विक टैक्नॉलजी दुनिया खुद बड़े बदलाव से गुज़र रही है। ऑटोमेशन, जेनरेटिव आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और नियर-शोरिंग, भारत की आई.टी. सफलता का आधार रहे पारंपरिक मजदूरी लाभ मॉडल को खत्म करने लगे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अब अपने देश के पास छोटी, अत्यधिक कुशल टीमों से ज़्यादा काम करवाना चाहती हैं। ऐसे में बड़े पैमाने पर ऑफ़शोर विस्तार की गुंजाइश घट सकती है, जब तक कि भारत तेज़ी से और व्यापक स्तर पर उच्च-स्तरीय उत्पाद विकास (हाई एंड प्रॉडक्ट डवलपमैंट) और बौद्धिक संपदा-आधारित सेवाओं में प्रवेश न करे। यह क्षेत्र अभी कुछ ही कंपनियों के हाथ में है।

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी भारत की बड़ी संरचनात्मक ताक़त माना जाता है। यू.पी.आई. जैसे प्लेटफ़ॉर्म ने लेन-देन की लागत (ट्रांज़ेक्शन कॉस्ट) घटाई है, पारदर्शिता बढ़ाई है, और अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण को तेज किया है, जिससे इस प्रक्रिया में वित्तीय समावेशन (फायनैंशियल इन्क्लूज़न) बढ़ा है। पर डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म अपने-आप उत्पादकता नहीं बढ़ाते। शिक्षा की गुणवत्ता, कौशल निर्माण और फिज़िकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में समानांतर सुधार के बिना डिजिटलाइज़ेशन से मिलने वाला लाभ सीमित रह सकता है। यह भी खतरा है कि डिजिटल दक्षता ज़्यादातर खपत और सेवाओं को ही बढ़ावा दे, न कि बड़े पैमाने के औद्योगिक और उत्पादक परिवर्तन को।

ई.वाय. का मानना है कि हाई ग्रोथ बनाए रखने के लिए तेज़ क्रैडिड बढ़ाना और कॉरपोरेट बॉन्ड बाज़ार को मजबूत करना अहम है। यहाँ भी एग्ज़ियूशन

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जैसलमेर में सरहद के पास संदिग्ध मौलवी गिरफ्तार

जैसलमेर, (नि.सं.)। भारत-पाकिस्तान सरहद पर जैसलमेर जिले में एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड ने एक संदिग्ध मौलवी को पकड़ा है। गणतंत्र दिवस से पहले हुई इस कार्रवाई ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं।

- **एंटी टैररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) कई दिनों से मौलवी की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए था।**

आतंकवादी गतिविधियों के खुफिया इनपुट के आधार पर टीम ने शनिवार को तनोट-किशनगढ़ क्षेत्र में कुरिया बेरी गांव में दबिश दी। मौलवी को जयपुर ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ होगी।

सूत्रों के अनुसार, आतंकवादी गतिविधियों के शक में पकड़ा गया मौलवी अलीखान बीकानेर में छत्तरगढ़

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)